W.T.O. की संरचना –

1995 में स्थापित विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निकाय मंत्रिस्तरीय वार्ता है, इसमें प्रत्येक देशों के वाणिज्यमंत्री भाग लेते हैं। इस मंत्रिस्तरीय वार्ता में बहुपक्षीय व्यापार समझौतों से सम्बन्धित सभी निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय सामान्यतः आम सहमति द्वारा लिए जाते हैं। सैद्धान्तिक रूप से प्रत्येक राज्य का मत समान होता है परन्तु व्यावहारिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र प्रतिबद्धी करते हैं। निर्णय आम सहमति द्वारा नहीं बल्कि गोपनीय बैठक में लिए जाते हैं ऐसा आलोचकों का आरोप है। अधिकांश विकासशील देशों को इन बैठकों में सम्मिलित ही नहीं किया जाता।

संरचना का द्वितीय स्तर –

मंत्रिस्तरीय वार्ता के पश्चात् W.T.O. के प्रतिदिन के कार्यों को सम्पादित करने हेतु निम्न निकायों का निर्माण किया गया। –

(A) सामान्य परिषद्
(B) विवाद निस्तारण परिषद्
(C) व्यापारिक नीति समीक्षा निकाय

सामान्य परिषद् W.T.O. की सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय है इसकी बैठक जिनेवा में नियमित रूप से चलती रहती है। इस परिषद् द्वारा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के आधार पर कार्य किया जाता है। इसके प्रतिनिधि राष्ट्रों के राजदूत या समान स्तर के अधिकारी होते हैं।

Scanned with CamScanner

विवाद निस्तारण का मूल अर्थ राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक विवादों का समाधान करना है। इस संस्था में भी सभी देशों के सदस्य सम्मलित होते हैं जबकि व्यापार नीति समीक्षा निकाय द्वारा राष्ट्रों के व्यापारिक नीतियों की समीक्षा होती है।

तृतीयक स्तर –

W.T.O. में सामान्य परिषद के अधीन व्यापारिक परिषद आते हैं, ये परिषद अलग-2 विषयों हेतु अलग-2 हैं। वस्तुओं की व्यापार परिषद का मूल कार्य है- व्यापार में वस्तुओं पर प्रशुल्कों के सामान्य समझौते की देख-रेख करना है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित परिषद का मूल कार्य बौद्धिक सम्पदा नियमों और आदर्शों को सुरक्षा करना है। जबकि सेवाओं की परिषद द्वारा सेवाओं के व्यापार की देखरेख की जाती है।

चतुर्थ / अंतिम स्तर –

व्यापारिक परिषद के भी अधीन निम्न परिषद काम करती है –

(A) वस्तु परिषद
(B) सेवा "
(C) विवाद निस्तारण पैनल

Scanned with CamScanner

उरुग्वे वार्ता
- कृषि
- टेक्सटाइल
- वरीयता व्यापार अधिमानात्मक व्यवहार

⇓

वस्तु + TRIPS + TRIMPS + सब्सिडी + डंपिंग

सिंगापुर बैठक

विकासशील — क्रियान्वयन मुद्दे अर्थात पहले किए गए वादों को पूर्ण किया जाए।

विकसित — नए मुद्दे (व्यापारिक) — ① सरकारी खरीद में पारदर्शिता मामला
② प्रतिस्पर्धा
③ निवेश के उपाय
④ "कृषि"

गैर व्यापारिक मुद्दे — ① श्रम मानक
② पर्यावरणीय मानक

Scanned with CamScanner

W.T.O. में भारत की भूमिका -

1. वर्तमान समय में कृषि मुद्दे पर विकसित देशों की नीतियों का विरोध करने में भारतीय भूमिका अच्छी है जिसमें चीन, ब्राजील अग्र हैं।

2. भारत ने, सब्सिडी आधार पर विभेदक व्यवहार को लागू करने पर बल दिया।

3. सिंगापुर मुद्दों का विरोध करने में भारत की भूमिका अच्छी है।

4. मल्टी फाइबर अरेंजमेंट को समाप्त करने तथा Trips प्रावधानों में छूट दिलाने में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है।

5. भारत अभी भी सेवा क्षेत्रों को पूर्णतः विकसित बनाने के लिए खोलने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि विकसित देश कृषि की सब्सिडी समाप्त नहीं करना चाहते।

6. पर्यावरणीय मुद्दों को व्यापार से जोड़ने तथा भारत ने आरम्भ से ही विरोध किया।

7. विकसित देशों की Anty Dumping नीति का भारत ने W.T.O. में प्रखर विरोध किया।

Scanned with CamScanner